कच्चे तेल का राजनीतिक गणित

अमेरिका ने ईरान पर पाबंदी बहाल कर पेट्रोलियम के बाजार की अस्थिरता को बढ़ाने के साथ ही भारत और चीन के लिए समस्या खड़ी कर दी है।

सौरभ चंद्र
पूर्व पेट्रोलियम सचिव
भारत सरकार

समीकरण तो उसी समय बदल गए थे, जब दो माह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा की थी कि उनका देश ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से बाहर निकल रहा है। तेहरान को घुटनों पर लाने के लिए जिस हथियार के इस्तेमाल का प्रस्ताव रखा गया, वह है उस पर फिर से आर्थिक प्रतिबंध लगाना। जाहिर है, इसका लक्ष्य ईरान द्वारा किए जा रहे कच्चे तेल के निर्यात को पूरी तरह रोकना तो नहीं, पर काफी हद तक कम करना है।

ईरान से होने वाले निर्यात में आधे से अधिक हाइड्रोकार्बन यानी पेट्रोलियम उत्पाद ही हैं। ईरान प्रतिदिन करीब 22 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है, जिसमें से लगभग 20 लाख बैरल वह रोजाना निर्यात करता है। इसलिए आकलन यही है कि निर्यात पर चोट करने से वह बुरी तरह प्रभावित होगा। पहले से ही आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहे इस मुल्क को अपनी शर्तों पर राजी करने का यह सबसे प्रभावी कदम माना जा रहा है। कयास यह भी है कि इससे सऊदी अरब को खासा महत्व मिलेगा, जो अमेरिका का विश्वसनीय सहयोगी है और पश्चिम एशिया की दबंग राजनीति में ईरान का प्रमुख प्रतिद्वंद्वी। ईरान से कच्चा तेल आयात करने वालों में चीन और भारत प्रमुख हैं। ये दोनों देश ईरान के कुल निर्यात का करीब आधा तेल खरीदते हैं। इसलिए ईरान पर प्रस्तावित एकतरफा प्रतिबंधों का इन दोनों देशों पर सबसे अधिक असर होने का अंदेशा है।

चित्रांकन : सुदर्शन मल्लिक

जाहिर है, इसने हमारे नीति-निर्माताओं की परेशानी बढ़ा दी होगी। उनके लिए सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि इन प्रतिबंधों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस हद तक असर होगा? अगर रोक लगी, तो अनिश्चितता बढ़ेगी ही। ऐसी संभावना दूर-दूर तक नहीं दिखती कि सऊदी अरब और अन्य तेल निर्यातक देश फौरी जरूरतों के मद्देनजर नवंबर, 2018 तक (प्रतिबंध के प्रभावी होने का संभावित समय) अपना उत्पादन 20 लाख प्रति बैरल रोजाना करने में सक्षम हो जाएं। फिर, सऊदी अरब द्वारा दबदबा कायम करने का विरोध ईरान और उनके सहयोगियों द्वारा किए जाने से क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव भी बढ़ सकता है। कीमतों का ऊपर-नीचे होना अस्थिरता का स्वाभाविक परिणाम माना जाता है। ताजा मामले में तेल के दाम बढ़ने की ही आशंका है, क्योंकि चीन व भारत वैश्विक स्तर पर जब तेल खरीदने निकलेंगे, तो इसके कारण आपूर्ति पर दबाव पड़ना तय है।

कच्चे तेल की ऊंची कीमत भारतीय रिफाइनिंग कंपनियों और भारत सरकार के बजटीय गुणा-भाग को प्रभावित करेगी। भारत अपनी जरूरत का 80 फीसदी से अधिक तेल आयात करता है। अगर वैश्विक बाजार में इसकी कीमतें बढ़ीं, तो व्यापार घाटा बढ़ना तय है। हालिया कुछ वर्षों को देखें, तो यह जरूरी नहीं है कि निर्यात में वृद्धि के अनुपात में आयात बिल में भी बढ़ोतरी हो। पूंजीगत खाते में आने वाले पैसे व्यापार के विस्तार और चालू खाते के घाटे की भरपाई शायद ही कर सकें। इसके लिए विदेशी मुद्रा भंडार को खर्च करने की जरूरत होगी, जिससे पहले से ही दबाव में चल रही रुपये-डॉलर की विनिमय दर यानी एक्सचेंज रेट और बढ़ेगी। इसके अलावा, तेल की बढ़ी कीमतें मुद्रास्फीति यानी महंगाई पर भी असर डालेगी और बढ़ी हुई एलपीजी (घरेलू गैस) व किरोसीन तेल सब्सिडी बिल से पार पाना सरकार के लिए खासा मुश्किल हो जाएगा। इससे पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क व वैट कम करने का दबाव भी बढ़ेगा। जाहिर है, यह सब कुछ चुनावी वर्ष में केंद्र व राज्य, दोनों सरकारों के वादों का इम्तिहान बन जाएगा।

इस परिस्थिति में भारत आखिर क्या कर सकता है? हर मुल्क अपने हितों के अनुरूप सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है। हालांकि हमारी घोषित नीति यही है कि हम एकतरफा प्रतिबंधों को मान्यता नहीं देते, फिर भी यह हमारे लिए फायदे की बात होगी कि हमें अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट मिले। यदि छूट नहीं मिली, तो भारतीय कंपनियां ईरान से कच्चे तेल का आयात करने में शायद ही उत्सुक होंगी। यदि वे आयात करती भी हैं, तो उन पर अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से बाहर किए जाने का खतरा होगा। ऐसा पहले किया भी गया है। लिहाजा एक अच्छी रणनीति यही हो सकती है कि इस मसले पर हम चीन के साथ मिलकर आगे बढ़ें। कच्चे तेल की कीमतें क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक होती हैं। इसमें तेजी आने से अमेरिकी तेल के दाम भी बढ़ेंगे। चूंकि नवंबर, 2018 में अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव्स (संसद का निचला सदन) का चुनाव होना तय है, इसलिए हम राष्ट्रपति ट्रंप की कारोबारी समझ के आधार पर अपने लिए आर्थिक प्रतिबंधों से कुछ छूट प्राप्त कर सकते हैं।

हमें आकस्मिक योजना भी बनानी होगी। गैर-मौद्रिक कारोबार यानी वस्तुओं के आदान-प्रदान वाली व्यवस्था बतौर विकल्प अपनाई जा सकती है। इस रणनीति में हमें आयात प्रबंधन पर खासा जोर देना होगा। साथ ही, व्यापार घाटे में वृद्धि को रोकने के लिए निर्यात बढ़ाने संबंधी उपायों पर भी अमल करने की जरूरत होगी। हमें निर्यातकों की मुश्किलों को प्राथमिकता के आधार पर दूर करना होगा। ईरान से आने वाले तेल के शोधन में लगी भारतीय कंपनियों के लिए इस ग्रेड के तेल का दूसरा स्रोत ढूंढ़ना काफी दुरूह काम होगा। इसलिए हमें अलग-अलग स्रोतों से तेल मंगवाने की व्यवस्था करनी होगी, जो इस मसले का एक आजमाया समाधान है।

इसी तरह, घरेलू मांग का उचित प्रबंधन भी हमें करना चाहिए। भारत जैसे देश में, जिसकी बिजली उत्पादन क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता, वहां तरल ईंधन द्वारा ऊर्जा उत्पादन पर जोर देना किसी विलासिता से कम नहीं है। इसे दूर करने के लिए बिजली उत्पादन करने वाली तमाम कंपनियों की कार्य-प्रणाली में सुधार लाना होगा। वैसे देखा जाए, तो यह मूल रूप से शासन से जुड़ा मसला है। खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों को चेताने के साथ ही जरूरी यह भी है कि सिंचाई पंपों के लिए सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित किया जाए।

कच्चे तेल के बाजार की अस्थिरता उसका एक अटल सत्य है। दुर्भाग्य से राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले ने इस अस्थिर बाजार की अस्थिरता और बढ़ा दी है। लिहाजा इस फैसले से पैदा होने वाले प्रतिकूल हालात से निपटने के लिए हमें तत्काल ठोस कदम उठाने होंगे।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)